Inspira-Journal of Commerce, Economics & Computer Science (JCECS)
ISSN : 2395-7069 (Print), General Impact Factor : 2.0546, Volume 03, No. 04, Oct.-Dec., 2017, pp. 395-399

भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण का प्रभाव (ग्रामीण विकास के विशेष संदर्भ में)

परमानन्द सुण्डा[G]

सार

गत् 8 नवम्बर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 500 और 1000 रूपये के नोटो को चलन से बाहर करने की घोषणा की गई। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन कर नई मुद्रा को प्रचलन में लाया जाता है, जिसे विमुद्रीकरण कहते है। विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना, भष्ट्राचार में कमी करना, आंतकवाद तथा नक्सलवाद को खत्म करना, जाली नोटो को निष्क्रिय करना तथा अर्थव्यवस्था को कैशलैस करना है। विमुद्रीकरण में बंद किए गए 500 व 1000 रूपये के नोटो का मूल्य 14.2 लाख करोड रूपये है जो कि 31 मार्च 2016 के आंकडो के अनुसार चलन में मौजूद कुल नोटो का 86.4 प्रतिशत है।

विमुद्रीकरण के निर्णय से भारतीय अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र तथा ग्रामीण विकास एक अहम घटक है। ग्रामीण परिवेश में कृषि, छोटे व्यापारी तथा कृषि संबंधित क्रियाएं जैसे यातायात, उद्योग आदि पर नकारात्मक प्रभाव पडा है। लेकिन उपर्युक्त के साथ – साथ किसान क्रेडिट कार्ड धारक को रूपे कार्ड, सरकार के फाइनेशियल इन्क्लूजन फंड से 2 प्वांइट आफ सेल मशीन फ्री तथा डिजिटल पेमेंट पर डिकांउट जैसी डिजिटल सुविधांए भी प्राप्त हुई है।इस शोध पत्र में विमुद्रीकरण के ग्रामीण विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा।

विमुद्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत सरकार किसी भी मूल्यवर्ग (कागजी मुद्रा) की मुद्राओं को अवैध घोषित कर चलन से बारह कर देती है इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है तथा पुरानी मुद्राओ की जगह नई मुद्राएं लाई जाती है। भारत सरकार द्वारा गत् 8 नवंबर 2016 को रू 500 एवं 1000 के नोंटो के चलन से बाहर करने की घोषणा की गई है। भारत में विमुद्रीकरण का उद्देश्य कालेधन, जानी नोट, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, उग्रवाद, अलगावाद, नक्सलवाद पर अंकुश लगाना तथा अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाना लक्ष्य रखा गया ।

नोटबंदी के फायदे

- विमुद्रीकरण से देश के आर्थिक विकास की रफ्तार और तेजी से बढने की उम्मीद है। 500–1000 रू के नोटो पर पांबंदी के बाद अर्थव्यवस्था के लूप होल्स (मसलन कालाधन, नकली नोट और शैडो बैकिंग आदि) भरेगे जिससे देश की अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी।

* शोधार्थी, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रंबध विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।

- राजनीति और चुनाव प्रक्रिया :– यह अघोषित सच है कि चुनाव में बडे पैमाने पर ब्लैक मनी खर्च की जाती है। चाहे टिकट खरीदने की बात हो, मतदाताओं को बाटने की बात हो या फिर प्रचार व अन्य लेनदेन। यह फैसला तब आया है जब एक साल के भीतर यू.पी., पंजाब गुजरात, गोवा, उत्तराखण्ड जैसे राज्यो में विद्यानसभा चुनाव होने है। ऐसे नेता जिन्हाने इन चुनावो के लिए ब्लैक मनी जमा की होगी वो उसका इस्तेमाल नही कर पाऐगे। ऐसे में चुनाव अपेक्षाकृत ज्यादा पारदर्शी होगे।
- गैर निष्पादित परिसंपतियों के उच्चतम स्तर और ऋण देने हेतु अनुपलब्ध धनराशी की गंभीर समस्या झेल रहे बैकिंग क्षेत्र को बडी मात्रा में नकदी प्राप्त हुई जिससे उनकी मौद्रिक तरलता में वृद्धि हुई। बैंको की मोद्रिक तरलता में हुई यह अभुतपूर्व वृद्धि अर्थव्यवस्था को कई तरीको से लाभावित्त करेगी।
  - इसका पहला बडा प्रभाव यह होगा कि बैंको द्वारा दिए जाने वाले ऋणो पर ब्याज की दरों में कमी आएगी।
  - बैकों में बढी हुई तरलता एवं घटी हुई ब्याज दरो के कारण नविन योजनाओं को गति मिलेगी तथा निवेश बढेगा।
- विमुद्रीकरण द्वारा बाजार में नकदी के अभाव के कारण मांग में कमी दर्ज की गई जिससे महंगाई में कमी आई। दिसम्बर 2016 में खुदरा महगाई दर घटकर 3.41 फीसदी पर आ गई।
- विमुद्रीकरण से सरकार के राजस्व सग्रंह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। वितमंत्रालय के आकडो के अनुसार दिसम्बर 2016 महिने में उत्पाद शुल्क में 31.6 फीसदी और सेवा कर संग्रह में 12.4 फीसदी वृद्धि हुई है। बढा हुआ राजस्व संग्रह निस्संदेह सरकार के वित प्रबंधन को लाभ पहुचाएगा।
- इससे वितीय क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढावा मिला। उपभोक्ताओं में डेबिटकार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई–वॉलेट जैसे भूगतान माध्यमों द्वारा भुगतान करने की प्रवृति में इजाफा हुआ। बढती हुई डिजिटल लेनदेन की प्रवृति वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता लाएगी। साथ ही यह लोगो को कैश लेकर चलने में होने वाली असुविधा से मुक्ति दिलाएगी। तथा केशलैस हस्तांतरण के द्वारा सभी हस्तातरण कत्ताओं को कर के दायरे में लाने का प्रयास किया गया है।
- आर. बी. आई. के पूर्व गवर्नर डी. सुब्बाराव के अनुसार ''विमुद्रीकरण अपने अन्य लाभों के साथ साथ निवेश में वृद्धि के लिए सकारात्मक माहौल पैदा करेगा, अपने परिणामों में यह महगाई में कमी लाएगा और महान कैश अर्थव्यवस्था की और ले जाएगा।
- रू 500 – 1000 पर पाबंदी लगाने से बैकं की दरे घटेगी जिससे की फ्लैट तथा जमीनो की कीमते कम होगी परिणामस्वरूप अपने घर का सपना देखने वाले लोगो के वाकई अच्छे दिन आएगे।
- नोट बदलने से नकली नाटो की समस्या पर लगाम लगी है क्योकी नए नोटो की सीरिज में सिक्योरिटी फीचर ज्यादा है। जिनकी नकल करना किसी व्यक्ति अथवा दूसरे देश के लिए बेहद मुश्किल होगा।
- विमुद्रीकरण सें आतकंवाद, उग्रवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद मे कमी आई है। रू 500 –1000 के नोटो पर पांबदी से आतकंवाद के वित्तीय स्त्रोत पर भी चोट लगी है। नकली नोट रद्दी हो गए। अवैध रूप से जमा कैश बेकार हो गया तथा आतकी सगंठनो में अवैध रूप से प्रयुक्त हो रही भारतीय मुद्रा पर लगाम लगी है। हाल ही में आतकवादी उग्रवादी और नक्सलवादी घटनाओं में आई कमी इस मत को पुष्ट भी करती है।

विमुद्रीकरण के नुकसानः इसमें कोई दो राय नही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विमुद्रीकरण के कई सकारात्मक परिणाम सामने आए परन्तु सरकार की ओर से एका एक अमल में लाई गई विमुद्रीकरण की इस प्रक्रिया ने संपूर्ण भारतीय आर्थिक परिदृष्य को आमूल– चूल रूप से प्रभावित भी किया। विमुद्रीकरण के इस कदम से कई नकारात्मक परिणाम भी सामने आए जो कि निम्न प्रकार हैः

- विमुद्रीकरण के कारण अर्थव्यवस्था में नकदी का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। एक अनुमान के मुताबिक विमुद्रीकरण से पूर्व जितनी करेंसी प्रचलन में थी उसमें 500 और 1000 रूपये के नोटो का हिस्सा लगभग 86 प्रतिशत था। ऐसे में एकाएक इन नोटो का प्रचलन रोक देने से नकद की कठिनाइयां आई। आर.बी.आई द्वारा नए नोटो की मांग से कम निर्गमन, कमजोर व सीमित बैकिंग ढांचा और बैंक के कुछ अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण नकदी का संकट विकराल होता चला गया।
- विमुद्रीकरण ने श्रम, भूमि व कर संबंधी आर्थिक सुधारो को अधर में लटका दिया क्योकि सरकार के लिए भी यह मुमकिन नही है कि वह एक साथ कई आर्थिक सुधारो के गति दे सके। तात्कालिक नकारात्मक प्रभाव जीएसटी का अधर में लटकना है। क्योकि यह 1 अप्रैल 2017 को प्रस्तावित होना था जो कि अब सम्भवतः जुलाई में होगा।
- विमुद्रीकरण से उत्पादन, खपत और निवेश में कमी आई है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलु उत्पाद का महत्वपूर्ण स्थान है जिसमें कृषि, विनिमार्ण, सेवा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2016 में भारत का सकल घरेलु उत्पाद लगभग 2300 अरब डालर था तथा भारत सरकार द्वारा 2016 – 17 में 7.6 प्रतिशत सकल घरेलु उत्पाद प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया जो कि सम्भवतः विमुद्रीकरण के कारण 7.1 प्रतिशत तक ही प्राप्त हो सकेगा।

अध्ययन के उदेश्यः शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैः

- विमुद्रीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करना है।
- विमुद्रीकरण ने ग्रामीण विकास को किस सीमा तक नकारात्मक तथा सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, को जानना है।

शोध प्रविधिः प्रस्तुत शोध में शोध पत्र की रचना विश्लेषणात्मक व वर्णनात्मक आधार पर की जाएगी। इस अध्ययन के लिए उद्देश्य बनाने , तुलना करने तथा निष्कर्ष निकालने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा तथा शोधपत्र से संबंधित संमक जर्नल, समाचार – पत्र व इनटरनेट के माध्यम से एकत्रित किये गए है।

विमुद्रीकरण का ग्रामीण विकास पर प्रभाव

- एसोचैम के अनुसार नोटबदी का सबसे बुरा प्रभाव सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगो पर पडा है। नोटबदी को बिना पुख्ता इंतजांम के किया जाना बहुत परेशानियों को जन्म दे रहा है। नोट बन्दी का सबसे ज्यादा नुकसान छोटी फर्मो को हुआ है, क्योकि ये नगद में व्यवहार करती है।
- देश की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सबसे महत्पूर्ण स्थान हैं। देश मे कुल रोजगार का 70 फीसदी रोजगार गांवो में है। देश के सकल घरेलु उत्पाद का 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र से आता है। इससे जाहिर है, कि 8 नवम्बर 2016 को प्रधान मंत्री के फैसले का सर्वाधिक प्रभाव ग्रामीण भारत पर हुआ। जब देश में नोटबदी का फैसला आया तो देश के किसानो के सामने रबी फसल की बुआई की बडी चुनौती थी जिन राज्यों में रबी बुआई की बडी चनौती थी। इस परिस्थिति ने कृषको के सम्मुख बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की अनुपलब्धता की समस्या उत्पन्न कर दी जिससे अधिकांश किसानो को पुराने पडे बीज से बुआई करनी पडी। परिणामस्वरूप कैश न होने के कारण उन्हे बाजार सुधरने का इतंजार करना पडा जिससे रबी की फसल बुआई में देरी हुई।
- ग्रामीण इलाकों में रोजगार के लिए केन्द्रीय स्कीम मनरेगा बुरी तरह प्रभावित हुई है। क्योकि नोटबंदी लागू होने के बाद से सरकार श्रमिको को यथा समय भुगतान करने में असमर्थ हुईं।

- भारतीय अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 90 प्रतिशत से अधिक है। जिसमें कार्यरत कामगार वर्ग अपनी मजदूरी या वेतन नकदी में प्राप्त करता है। ऐसे में एकाएक उपजे नगदी संकट ने इन्हे अत्यधिक प्रभावित किया इसका प्रभाव इस स्तर तक देखा गया कि महानगरो व उनके उपनगरीय तथा बडे शहरो में रेह्डी – पटरी वाले,छोटे मोटे व्यापार करने वाले तथा दैनिक मजदूर अपने गावं लोटने को विवश हो गए।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बडा प्रभाव रिवर्स माइग्रेशन का दिखाई दिया। शहरो में रियल एस्टेट सेक्टर और उद्योगो में श्रमिको को भुगतान में दिक्कतो के चलते लोग गांव का रूख करने पर मजबूर हो गए। नोटबंदी लागू होने के बाद से गांव पलायन कर चुके श्रमिको को देश में एक बार फिर कैश की किल्लत खत्म होने का इतजार है।
- नोटबदी के दौर में सबसे बडी समस्या ग्रामीण क्षेत्रो में पुराने नोट जमा कराने तथा नये नोट निकालने में हुई। देश की कुल जनसख्या का लगभग 70 फीसदी गांवो में रहता है लेकिन उन्हे महज कुल एटीएम मशिनो का 45 प्रतिशत ही उपलब्ध है तथा एटीएम से पैसै निकालने के लिए उन्हे 5 से 25 किमी की यात्रा करनी होती है। इसके बावजूद 8 नवम्बर 2016 के बाद ग्रमीण इलाको में एटीएम और बैंक तक पैसा पहुचाने में सबसे ज्यादा समय लगा।
- नोटबदी से पहले भी देश में कालेधन छिपाने के लिए ग्रमीण इलाको में खेती की जमीन के खरीद फरोख्त का मायाजाल चलता था नोटबदी लागू होने के बाद एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में जनधन खातो का गलत इस्तेमाल करते हुए कालेधन को छिपाने की भरपुर कोशिश की गई।

खोज एवं सुझावः विमुद्रीकरण के मूल्याकन अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि विमुद्रीकरण ने भारत की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से ही नही अपितु नकारात्मक रूप से भी प्रभावित किया है भारत में कुल जनसंख्या के लगभग 70 फीसदी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अतः यह कहना उचित होगा कि शहरी क्षेत्रो की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश विमुद्रीकरण से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। चुकीं विमुद्रीकरण नगदी से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, अतः कहा जा सकता है कि ग्रामीण परिवेश में अर्थिक क्षेत्र के साथ– साथ सास्कृतिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र भी प्रभावित हुआ है। क्योकि ग्रामीण लोग अधिकांश कार्य नगद में करते है। विमुद्रीकरण से देश में ग्रामीण मजदूर वर्ग के रोजगार विहिन रहने, छोटे छोटे व्यवसायो के ठप होने तथा सामाजिक कार्यक्रमों के बाधित होने जैसे कई प्रभाव हुए है।

विमुद्रीकरण का निर्णय सरकार सरकार की एक सकारात्मक सोच का प्रदर्शन करता है परन्तु इसके साथ साथ सरकार को नोटो की मांग के अनुसार पूर्ति, कमजोर व सीमित बैकिंग ढाचें को दूरस्त करना तथा बैकों में कार्यस्थल पर भ्रष्टाचार को रोकना आदि उपाय साथ साथ में किए जाने चाहिए थे। साथ ही ग्रामीण लोगो के लिए विशेषतः किसानो को फसलो की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस भी दिए जाने,किसान क्रेडिट कार्ड के तहत वितरित ऋण पर ब्याज वसूली में छूट दिए जाने, मनरेगा के कार्य दिवसो में वृद्धि करने तथा सम्भावित अतिरिक्त कर सग्रंह से सामाजिक कल्याण की नई योजना शुरू करने जैसे उपाय भी करना आवश्यक है जिससे कि विमुद्रीकरण से होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सकता अथवा समाप्त किया जा सकता है विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता, कालाधन की समाप्ति, आतकंवाद पर रोक तथा जाली नोटो को निष्क्रिय करने की सरकार की एक अनुठी पहल है।

निष्कर्षः विमुद्रीकरण द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है, जिससे की लोगो को नगद साथ लेकर चलने वाली कठिनाईयो से मुक्ति मिल सके तथा वित्तीय तंत्र में पारदर्शिता हो। वितिय क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन को बढावा देना भी विमुद्रीकरण का एक अहम उद्देश्य रहा है। साथ ही कालाधन आतकंवाद तथा जाली नोटो पर रोक भी इसके मुख्य उद्देश्य हैं चूंकि भारत की अधिकाश जनसंख्या गांवो में निवास करती है। अतः साधारण शब्दो में कह सकते है कि ग्रामीण क्षेत्र तथा इस क्षेत्र का

विकास मुख्यत विमुद्रीकरण से प्रभावित हुआ है। ये प्रभाव सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनो ही रूप में पडा है। लेकिन इसे सही रूप में माप पाना कठिन कार्य है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- आर्थिक समीक्षा (भारत सरकार) 2016 –17
- दृष्टि (द विजन), कर्रेट अफेयर्स टुडे, मार्च 2017, अंक 10
- समाचार पत्र, द हिन्दु, इडियन एक्सप्रेस, टाइम्स आफ इण्डिया, इकानॉमी टाइम्स, जन शक्ति ,दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका।
- डां. कविता राव, डां. सुधाशु कुमार एवं अन्य, ''डिमोनेटाइजेशनः इम्पेक्ट ऑन द इकोनॉमी, एन. पी. एफ. पी., पेपर नम्बर 182, नई दिल्ली, 2016
- इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली , 2016
- अरिधमं चन्दा, नोट्स ऑन डीमोनेटाइजेशन, दिसम्बर 2016
- पी.टी. आई. (2016), डिमोनेटाइजेशन विल बेनिफिट्स इकोनोमी इन लोग रनं।

❍❍❍